SHRI ANAND SHARMA (Himachal Pradesh): Sir, Formalin is normally used in the preservation of dead bodies. ...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: That is why I am asking him to take note of it. He can't answer. ... (*Interruptions*)... Mr. Bhupender Yadav, do you wish to associate yourself with it?

SHRI BHUPENDER YADAV (Rajasthan): Sir, I wish to associate myself with the matter raised. ...(Interruptions)... I also wish to say something. ...(Interruptions)...

SHRI ANAND SHARMA: Sir, the Minister must answer. ... (Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: But he must be ready to give the answer. Just now I allowed the Member to raise it and I have asked the Minister to take note of it. He would take note of it and then, if he is ready, he would give the reply normally. Otherwise, he has to collect the information and give it. Moreover, it is not mandatory in this Hour. ...(Interruptions)...

श्री भूपेन्द्र यादव (राजस्थान)ः सभापति महोदय, भैंने Zero Hour के starting में एक point of order के लिए कहा था।

श्री सभापतिः नहीं, अभी नहीं। मुझे लिस्ट पूरी करने दीजिए।

श्री भूपेन्द्र यादवः पांच मिनट रह गए हैं, अगर आप मुझे इजाज़त दे दें।

श्री सभापितः थोड़ा orderly चल रहा है तो प्वाइंट ऑफ ऑर्डर उठाकर डिसऑर्डर को करने से नुकसान होगा। आज मेरा सबसे अनुरोध है, हाउस ऑर्डर में चल रहा है, कृपया आप आगे बढ़िए और काम पूरा करिए। आपके प्वाइंट ऑफ ऑर्डर को मैं बाद में जरूर सुनुंगा। श्री राकेश सिन्हा।

Need for welfare and holistic development of nomadic tribes in the country

श्री राकेश सिन्हा (नाम निर्देशित): सभापित महोदय, में एक ऐसे विषय की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि विमुक्त जातियां, जिन्हें घुमन्तू जातियां कहते हैं, उनकी संख्या देश में आठ करोड़ से अधिक है। इनके ऊपर दादा इदाते कमीशन का गठन हुआ था। दादा इदाते कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। ये घुमन्तू जातियां ऐसी हैं, जिसमें लगभग 100 जातियां आती हैं। इनके ऊपर किसी भी दल या समाज के अन्य लोगों का ध्यान नहीं जा पा रहा है क्योंकि ये अलग-अलग स्थानों पर घूमते हैं। इनके बच्चों की शिक्षा, इनका पुनर्वास, इनका रोज़गार - ये सभी मुद्दे आज हमसे अपेक्षित हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इन जातियों के लिए सरकार इस आयोग की अनुशंसा का क्या कर रही है? क्या सरकार इनके पुनर्वास के लिए एक स्थायी आयोग बनाने जा रही है? सौभाग्य से कुछ एनजीओज़ इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिनमें से एक "भटके विमुक्त विकास परिषद" नाम का एनजीओ है जो काम कर रहा है, वह अपने स्तर पर उनके पुनर्वास की व्यवस्था कर रहा है। मेरा सरकार से इतना ही आग्रह और अनुरोध है कि इन जातियों के लिए एक स्थायी आयोग का गठन किया जाए, दादा इदाते कमीशन की रिपोर्ट को स्वीकार किया जाए और जल्दी से जल्दी इनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए।

श्री अमर शंकर साबले (महाराष्ट्र)ः महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री रिव प्रकाश वर्मा (उत्तर प्रदेश)ः महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

महंत शम्भुप्रसादजी तुंदिया (गुजरात)ः महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री भूपेन्द्र यादवः महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री नीरज शेखर (उत्तर प्रदेश)ः महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

SHRIMATI ROOPA GANGULY (Nominated): Sir, I too associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI MANISH GUPTA (West Bengal): Sir, I too associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY (West Bengal): Sir, I too associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. VIKAS MAHATME (Maharashtra): Sir, I too associate myself with the matter raised by the hon. Member.

श्री सभापतिः कुमारी शैलजा, आपके नाम का नोटिस है।

KUMARI SELJA (Haryana): Sir, I asked in the morning that...

MR. CHAIRMAN: You must be knowing the subject.

KUMARI SELJA: Yes. Sir.

Floods in agricultural areas of Haryana

कुमारी शैलजाः सभापित महोदय, अभी इस बारिश के मौसम में hilly regions में बहुत ज्यदा बारिश हुई है और यमुना में बहुत ज्यादा पानी आया है। जो hilly regions हैं, वहां पहाड़ों से पानी आता है। जो हथिनी कुंड बैराज है, वहां से हरियाणा को पानी release करना पड़ता है और वह दिल्ली की ओर यमुना में बह जाता है। जब ज्यादा पानी आ जाता है तो जगह-जगह पर breaches हो जाते हैं। हरियाणा में हज़ारों एकड़ भूमि इस पानी के नीचे आ गयी है और हमारी बहुत सारी फसल वहां पर बर्बाद हो गयी है, इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि जिन किसानों की फसल बर्बाद हुई है, उन्हें उचित मुआवज़ा मिलना चाहिए और सही समय पर मुआवज़ा मिलना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो भी प्रॉपर्टी destroy हुई है, उसके लिए भी समय पर मुआवज़ा दिया जाए।